SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह बैगा जनजाति की आजीविका में वन संसाधनों की भूमिकाः छत्तीसगढ़ के कवर्धा ज़िले का एक सामाजिक, आर्थिक अध्ययन

घुरवा राम श्याम, शोधार्थी, **आर. एन. सिंह,** पी–एचडी., शोध निर्देशक, अर्थशास्त्र विभाग, पूर्व प्राचार्य
शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors

घुरवा राम श्याम, शोधार्थी
आर. एन. सिंह, पी–एचडी., शोध निर्देशक
E-mail : raghushyam90@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 16/08/2025
Revised on : 14/10/2025
Accepted on : 23/10/2025
Overall Similarity : 00% on 15/10/2025

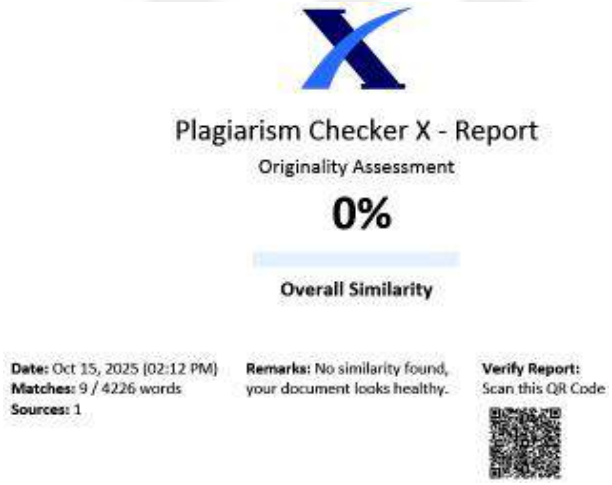

शोध सार

यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के कवर्धा ज़िले के विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) बैगा समुदाय की आजीविका में वन संसाधनों (लघु वनोपज/NTFP– नॉन टिम्बर फारेस्ट प्रोडक्ट) की बहु–आयामी भूमिका का सामाजिक–आर्थिक आंकलन प्रस्तुत करता है। जून से दिसम्बर 2022 में देवानपटपर, अधचरा और दमगढ़, इन तीन बैगा–बहुल ग्रामों के 150 परिवारों से संरचित साक्षात्कार, समूह आधारित चर्चा और सहभागी अवलोकन द्वारा प्राथमिक आँकड़े संकलित किए गए; द्वितीयक स्रोतों में जनगणना 2011, वन विभाग तथा जनजातीय शोध संस्थान की रिपोर्टें सम्मिलित की गयी है। समेकित NTFP–प्रोफ़ाइल दर्शाती है कि संग्रहण–संरचना में तेंदूपत्ता (लगभग 46.97 प्रतिशत) और महुआ (लगभग 31.86 प्रतिशत) का संयुक्त योगदान करीब 79 प्रतिशत है, जबकि चार/चरौंजी (लगभग 8.79 प्रतिशत) का संग्रह–हिस्सा अपेक्षाकृत कम होते हुए भी MSP–आधारित राजस्व (लगभग 74.73 प्रतिशत) में सर्वाधिक है– जो उच्च "मूल्य–घनत्व" का संकेत देता है। महुआ का गृह–उपभोग (लगभग 88.28 प्रतिशत) अत्यधिक पाया गया, जो पोषण–सुरक्षा, सांस्कृतिक उपयोग और मौसमी जोखिम–शमन में इसकी केंद्रीयता को पुष्ट करता है। सर्वेक्षित आंकड़ों के अनुसार 80 प्रतिशत परिवार वन पर उच्च निर्भर तथा 75 प्रतिशत परिवार वनोपज–आधारित नक़द आय पर आश्रित हैं; 60 प्रतिशत परिवारों ने दशक में निर्भरता में कमी का संकेत दिया, जो मनरेगा, कृषि–मजदूरी और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से आंशिक विविधीकरण को दर्शाता है तथापि, वन–अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन, उचित मूल्य–निर्धारण, बाज़ार मध्यस्थता/भुगतान–पारदर्शिता तथा शिक्षा–स्वास्थ्य पहुँच जैसी बाधाएँ बनी रहीं। अध्ययन सुझाता है कि सामुदायिक

/सामूहिक अधिकारों का सुदृढ़ अनुपालन, महिला–SHG आधारित NTFP–प्रसंस्करण, समय पर भुगतान व मूल्य–सूचना, और सहभागी वन–प्रबंधन से बैगा आजीविका की स्थिरता, आय–वृद्धि तथा सांस्कृतिक–पारिस्थितिक निरंतरता सुदृढ़ की जा सकती है; साथ ही, प्रस्तावित मापनयोग्य संकेतक (उत्पाद वार मूल्य–श्रृंखला, मौसम आधारित कार्य, भुगतान विलंब) अन्य विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में यह स्थानीय संदर्भानुकूल आधार प्रदान करते हैं।

मुख्य शब्द

विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा जनजाति, लघु वनोपज, आजीविका, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सहभागी वन–प्रबंधन.

परिचय

भारत के वनवासी जनजाति समुदायों का सामाजिक–आर्थिक जीवन परंपरागत रूप से जंगलों से गहराइ से जुड़ा रहा है। विशेष रूप से 'बैगा जनजाति' जो भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय समूह (PVTG) में वर्गीकृत हैं, इनका जीविकोपार्जन, खाद्य–सुरक्षा, औषधीय ज्ञान, आवासीय सामग्री और उत्सव–अनुष्ठानों तक में वन संसाधनों की प्रमुख भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ का कबीरधाम (कवर्धा) जिले के पंडरिया और बोड़ला विकासखंड में बैगा जनजातीय बस्तियों की सघन उपस्थिति पाई जाती है। अपेक्षाकृत उच्च पहाड़ी वनावरण और विविध लघु वनोपज (NTFPs) की उपलब्धता के कारण इस शोध पत्र के लिए उपयुक्त शोध क्षेत्र प्रदान करता है। स्थानीय भौगोलिक, पठारी–वनीय स्थलाकृति, वर्षा के मौसमी चक्र व वृष्टि छाया क्षेत्र, और साल (सरई), सागौन, साजा, बीजा जैसे मिश्रित वनों ने सदियों से बैगा समुदाय के उत्पादन, उपभोग और विनिमय व्यवहार को आकार दिया है। वन संसाधनों की भूमिका केवल आय तक सीमित नहीं है; यह पोषण–सुरक्षा (महुआ, जंगली फल/कंद, शहद, तेंदू पत्ता, इमली, चार, पिहरी (फुटू), पारंपरिक चिकित्सा (हर्रा, बेहड़ा, आँवला, गिलोय), आवासीय सामग्री (बाँस, लकड़ी, घास) और सांस्कृतिक धार्मिक आस्था ("वन देवता", प्रकृति–पूजन, गोदना–परंपरा) का भी आधार है। इस प्रकार बैगा–वन सम्बंध एक संस्कृति पारिस्थितिकी का रूप लेते हैं, जहाँ आजीविका और संस्कृति परस्पर–निरपेक्ष नहीं बल्कि एक दुसरे पर सह–निर्भर हैं। महुआ जैसे उत्पाद घरेलू उपभोग, पोषण और अनुष्ठानों में प्रमुख स्थान रखते हैं, जबकि चार (चरौंजी), पिहरी (फुटू), इमली जैसे उत्पाद अपेक्षाकृत उच्च बाज़ार–मूल्य के कारण नक़द आय के प्रमुख स्रोत बनते हैं; तेंदूपत्ता व्यापक संग्रहण–आधार के बावजूद विशेष संस्थागत क्रय–तंत्र से संचालित होता है।

समकालीन नीतिगत/पारिस्थितिकीय परिवर्तन; जैसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980, वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, बाज़ारीकरण, मनरेगा, तथा शिक्षा–स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार ने बैगा की निर्भरता–प्रकृति और आय–स्रोतों के मिश्रण में बदलाव उत्पन्न किए हैं। एक ओर FRA ने व्यक्तिगत/सामुदायिक अधिकारों की संभावनाएँ खोली हैं, दूसरी ओर क्रियान्वयन में असमता, मूल्य–निर्धारण की अपारदर्शिता, भुगतान–विलंब और मध्यस्थ–निर्भरता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जलवायु–सांवेग (मौसमी, सूखा/न्यून वर्षा) NTFP की उपलब्धता और कीमतों पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, जिससे घरेलू जोखिम–विविधीकरण (मनरेगा, कृषि–मजदूरी, सूक्ष्म–उद्यम) का महत्व बढ़ा है।

इस अध्ययन का उद्देश्य बैगा आजीविका में वन संसाधनों की भूमिका का समग्र मूल्यांकन करना है जिसमें (i) NTFP का संग्रह सूचि, (ii) गृह–उपभोग बनाम बाज़ार–विक्रय (MSP/औपचारिक आय), और (iii) सामाजिक–आर्थिक संकेतक (अधिकार–स्थिति, सेवा–पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवास) शामिल हैं। अध्ययन कवर्धा ज़िले के देवानपटपर, अधचरा और दमगढ़, इन तीन बैगा–बहुल ग्रामों के 150 परिवारों पर आधारित है (जून 2022), जिनसे संरचित साक्षात्कार, विषय केन्द्रित सामूहिक चर्चा और सहभागी अवलोकन के माध्यम से प्राथमिक आँकड़े संकलित किए गए। द्वितीयक स्रोतों में जनगणना, वन विभाग और जनजातीय अनुसंधान संस्थान की रिपोर्टें सम्मिलित हैं। विश्लेषण के लिए सतत पोषणीय आजीविका (SLF) तथा संस्कृति पारिस्थितिकी/सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया है, ताकि परिणाम नीति–निर्माताओं के लिए साक्ष्य–समर्थ, समुदाय–केंद्रित अनुशंसाएँ प्रस्तुत कर सकें; जैसे FRA का प्रभावी क्रियान्वयन, महिला–SHG आधारित NTFP–प्रसंस्करण, बाज़ार–सूचना, भुगतान की

पारदर्शिता, और सहभागी वन–प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण। अंततः लक्ष्य है कि बैगा समुदाय की पोषण–सुरक्षा, सांस्कृतिक निरंतरता और आय–स्थिरता तीनों को साथ लेकर चलने वाली सतत एवं न्यायसंगत नीतियाँ विकसित की जाएँ।

साहित्य समीक्षा

मध्य भारत की आदिवासी संस्कृति पर वेरियर एल्विन की 'The Baiga' तथा खाका के कार्य यह रेखांकित करते हैं कि बैगा समुदाय का सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन गहन रूप से वन–पारिस्थितिकी से सह–निर्भर है। जीविकोपार्जन, अनुष्ठान, उपचार और ज्ञान–उत्पादन सभी में जंगल केंद्रीय है। NTFP अर्थशास्त्र पर अर्नोल्ड और कैम्पवेल तथा चोपड़ा और काडेकोदी ने दिखाया कि लघु वनोपज केवल नक़द आय नहीं, बल्कि पोषण–सुरक्षा, सामाजिक पूँजी और जोखिम–विविधीकरण का स्तंभ हैं। ग्रामीण गरीबी–चक्र को नरम करने में इनका मौसमी "सुरक्षा–जाल" प्रभाव महत्वपूर्ण है। भारतीय संदर्भ में JFM/CFM ने समुदाय–आधारित प्रबंधन की संस्थागत आधार–रचना दी, जबकि FRA, 2006 ने व्यक्तिगत/सामुदायिक अधिकारों की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की; तथापि, क्रियान्वयन–असमता, बाज़ार–मध्यस्थता और भुगतान–पारदर्शिता की कमी, वनोपज गुणवत्ता–ग्रेडिंग/भंडारण की अपर्याप्तता जैसी बाधाएँ लगातार दर्ज हुई हैं। स्थानीय तौर पर बैगा जनजाति के समग्र सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक विशेषताओं पर अध्यन हरि शंकर और अनिल उल्लेखित करते है कि बैगा की आजीविका में लघु वनोपाज की विशेष भूमिका है।

इस शोधपत्र का वैचारिक रुपरेखा तीन पूरक दृष्टिकोणों पर आधारित है। प्रथम, सतत् आजीविका ढाँचा (SLF, 1999), जो मानव, प्राकृतिक, भौतिक, वित्तीय और सामाजिक; इन पाँच पूँजियों के अंतःक्रियात्मक संतुलन पर बल देता है। बैगा संदर्भ में प्राकृतिक पूँजी (वन/लघु वनोपज) और सामाजिक पूँजी (समुदाय/SHG नेटवर्क) निर्णायक पाई गईं, जबकि मानवीय, भौतिक व वित्तीय पूँजी उनके प्रभाव को सक्षम/सीमित करती हैं। द्वितीय, पारिस्थितिकी–सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जो संस्कृति और पारिस्थितिकी की सह–उत्पत्ति को रेखांकित करता है– महुआ, संस्कार, "वन देवता, ग्राम देवता" और पारंपरिक औषधीय ज्ञान जैसे तत्व केवल प्रतीक नहीं, बल्कि संसाधन–उपयोग की मानक–व्यवहार प्रणाली हैं; ये पोषण, उपचार और अनुष्ठानों को वन–निर्भर जीवन से जोड़ते हैं। तृतीय, सहभागी विकास राजनीतिक पारिस्थितिकी का परिप्रेक्ष्य, जो बताता है कि नीतियाँ, बाज़ार–संरचनाएँ और अधिकार–व्यवस्थाएँ (जैसे FRA, MSP, JFM/CFM) शक्ति–संबंधों के माध्यम से स्थानीय आजीविका को कैसे आकार देती हैं; यहीं से मूल्य–शृंखला की असमानताएँ (कोटि निर्धारण/भुगतान/मध्यस्थता) और शासन–व्यवस्था की खाइयाँ उजागर होती हैं, तथा सह–निर्णय, पारदर्शिता और महिला–SHG आधारित उद्यमिता जैसे सुधार–मार्ग चिन्हित होते हैं।

कवर्धा के बैगा संदर्भ में उत्पाद विशिष्ट मूल्य शृंखलाएँ (महुआ, तेंदूपत्ता, चार), MSP की वास्तविक उपलब्धता/पारदर्शिता, पारंपरिक ज्ञान भूमिकाएँ, और मौसम आधारित आय–स्थिरता के संबंध का समेकित, क्षेत्र–विशेष विश्लेषण सीमित मिला; यही इस अध्ययन का केन्द्रीय योगदान है।

अध्ययन क्षेत्र की विशेषता

कबीरधाम (कवर्धा) जिला छत्तीसगढ़ के मध्य–पश्चिमी भाग में स्थित है, जहाँ सतपुड़ा की परिधीय पहाड़ियाँ और पठारी–वनीय भौगोलिक मिश्रित रूप में मिलती हैं। जलवायु उष्णकटिबंधीय और वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 800–1000 मि.मी. के बीच रहती है। जिले का लगभग 40 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है, जिसमें साल, साजा, बीजा, हर्रा–बेहड़ा, बाँस इत्यादि प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जनजातीय परिदृश्य में बैगा के साथ गोंड और अगरिया समुदायों की भी उपस्थिति उल्लेखनीय है। स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार सीमांत वर्षा–आधारित कृषि, लघु वनोपज (NTFP) का संग्रह/विक्रय, कृषि–मजदूरी तथा थोडा बहुत पशुपालन है; मौसमी और बाज़ार से दूरी आजीविका–जोखिम को प्रभावित करती हैं।

इस अध्ययन के लिए कवर्धा जिले में बैगा–बहुल तीन ग्राम– देवानपटपर, अधचरा और दमगढ़ चुने गए। ये गाँव मुख्यतः पंडरिया परिक्षेत्र के वनीय–ग्रामीण संक्रमण क्षेत्र में आते हैं, जहाँ सड़क/बाज़ार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य–शिक्षा सुविधाओं तक पहुँच अपेक्षाकृत सीमित है। स्थलाकृतिक विविधता (ऊँची पहाड़ियाँ, नालों–खेतों का जाल) और वन–निकटता के कारण यहाँ महुआ, तेंदूपत्ता, चार (चरौंजी) सहित NTFP की उपलब्धता समुदाय की आजीविका संरचना को प्रत्यक्ष रूप से आकार देती है। जून से दिसंबर 2022 में इन तीन ग्रामों से 150 बैगा परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, जिनसे संग्रह, गृह–उपभोग, MSP/विक्रय, तथा FRA–संबंधित अधिकार स्थिति पर प्राथमिक आँकड़े संकलित हुए। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र एक विशिष्ट पारिस्थितिकीय सांस्कृतिक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जहाँ वन संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और बाज़ार–संरचनाएँ साथ–साथ समुदाय की आजीविका को निर्धारित करती हैं।

कार्यविधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक–विश्लेषणात्मक अभिकल्पन पर आधारित सर्वेक्षण गुणात्मक अन्वेषण है। सर्वेक्षण कार्य जून से दिसम्बर 2022 से तक सर्वेक्षण कार्य संपन्न किया हुआ है। अध्ययन–क्षेत्र कवर्धा (कबीरधाम) के तीन गाँवों देवानपटपर, अधचरा, दमगढ़ का चयन किया गया है। आंकड़ों के लिए उदेव्श्यूर्ण न्मुनाकरण कर 150 बैगा परिवार को (बैगा–घनत्व, वन–निर्भरता, दुर्गमता, बाजार से दूरी) के आधार पर लिया गया है।

इस अध्ययन में आँकड़ों संग्रह हेतु (i) संरचित प्रश्नावली का उपयोग; आय–मिश्रण, NTFP (संग्रह/गृह–उपभोग/MSP–विक्रय), शिक्षा–स्वास्थ्य तथा FRA–स्थिति (ii) FGD (बुजुर्ग, महिलाएँ, वन–अधिकार समिति), (iii) सहभागी अवलोकन (संग्रह–प्रक्रिया, हाट/मंडी व्यवहार) और (iv) प्रमुख सूचनादाता साक्षात्कार (शिक्षक/स्वास्थ्यकर्मी/वन अधिकारी/NGO) का उपयोग किया गया। प्रमुख चर के रूप में; संग्रहण–प्रतिशत (कुल NTFP संग्रह में उत्पाद–वार हिस्सा), उपभोग–प्रतिशत (कुल घरेलू NTFP–उपयोग में उत्पाद–वार हिस्सा) और MSP–राजस्व–प्रतिशत (कुल औपचारिक/MSP आय में उत्पाद–वार हिस्सा); ध्यान रहे, तीनों प्रतिशत अपने–अपने चर पर आधारित हैं, इसलिए ये रूपरेखा संकेतक हैं। विश्लेषण में वर्णनात्मक आँकड़े, तुलनात्मक प्रोफ़ाइल और विषयगत व्याख्या अपनाई गई, जहाँ उपयुक्त वहाँ आय–घनत्व और उपयोग अभिविन्यास की व्याख्या की गई। नैतिकता के तहत पूर्व–सूचित सहमति, अनामिकीकरण और सांस्कृतिक संवेदनशीलता बरती गई, तथा सामुदायिक प्रतिक्रिया–सत्र के माध्यम से निष्कर्षों का सत्यापन किया गया।

शोध अभिकल्प
⇩
(शोध क्षेत्र गाँवः देवानपटपर, अधचरा, दमगढ़)
⇩
(उदेश्यपूर्ण नमूना 150 परिवार)
⇩
(आँकड़ा संग्रह)
⇩
- प्रश्नावली
- समूह केन्द्रित परिचर्चा (FGD)
- अवलोकन
- गृह प्रमुख से साक्षात्कार (KII)

(आंकड़ा परिष्करण/ आंकड़ा कुंजिकरण)
⇩
(विश्लेषणः तालिकाएँ, संकेतक प्रदर्शन)
⇩
(लेखन व प्रेषण + सामुदायिक प्रतिपुष्टि + नैतिक अनुपालन)

परिणाम

तालिका–1.1 बताती है कि 80 प्रतिशत बैगा परिवार भोजन, ईंधन और नक़द आय तीनों के लिए वनों पर ऊँची निर्भरता रखते हैं साथ ही, 60 प्रतिशत परिवारों ने पिछले दशक में निर्भरता में कमी का संकेत दिया; इसे 'वन उपज का छोड़ना' नहीं, बल्कि मनरेगा, कृषि–मजदूरी, पलायन, छोटे उद्यम और सरकारी योजनाओं के सहारे विविधीकरण से है। 75 प्रतिशत परिवार वनोपज बेचकर नक़द आय प्राप्त करते हैं। मौसमी, बाज़ार दूरी और मध्यस्थ या बिचौलियों पर निर्भरता के कारण जोखिम बना रहता है। केवल 40 प्रतिशत को व अधिकार अधिनियम (FRA) के अंतर्गत भूमि पट्टा अधिकार प्राप्त होना इसके क्रियान्वयन व असमता और प्रक्रियाओं की धीमी गति को दर्शाता है। 20 प्रतिशत परिवार उच्च–शिक्षा हेतु दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर व अन्य की और प्रवास करते हैं, जो इनकी आकांक्षा को दर्शाता है, पर गुणवत्ता शिक्षा/आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति और भाषिक–सहायता की कमी भी उजागर करता है। समेकित रूप से इसकी सूची उच्च आधार निर्भरता और उभरता विविधीकरण दिखाती है; नीति–पक्ष पर अधिकार–सुनिश्चितीकरण, बाज़ार–पारदर्शिता, परिवहन भुगतान सुधार और सेवा–पहुंच (शिक्षा–स्वास्थ्य/रोजगार) को मज़बूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

तालिका 1: देवनपटपर, अधचरा और दमगढ़ में वनों पर आजीविका–निर्भरता एवं सामाजिक–आर्थिक संकेतक (प्रतिशत)

क्र.	संकेतक	उत्तर (प्रतिशत)	टिप्पणी
1.	वनों पर पूर्ण निर्भरता	80	भोजन–ईंधन–आय तीनों हेतु वन
2.	निर्भरता में कमी (10 वर्ष)	60	योजनाओं/विविधीकरण से कुछ शिफ्ट
3.	वनोपज बेचने से आय	75	मुख्यतः तेंदूपत्ता, महुआ, चार
4.	भूमि अधिकार (FRA)	40	प्रक्रियागत/विवाद शेष
5.	उच्च शिक्षा हेतु प्रवास	20	सामाजिक–आर्थिक बाधाएँ

*(**स्त्रोतः** प्राथमिक समंक)*

उच्च आधार–निर्भरता के साथ–साथ विविधीकरण के संकेत; अधिकार/सेवा–पहुंच में अंतराल

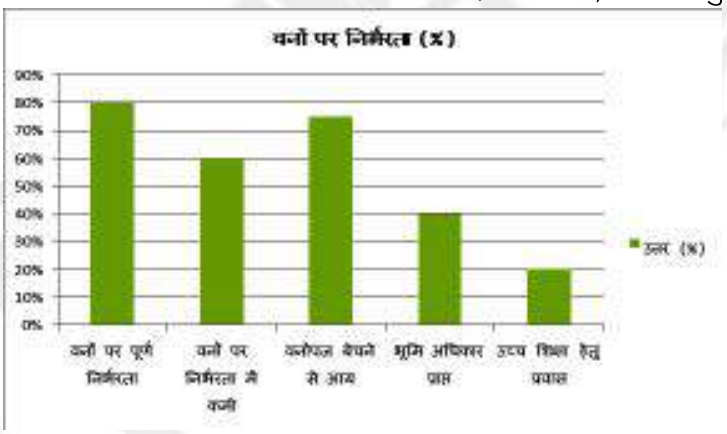

तालिका–2 देवानपटपर NTFP संग्रहण में तेंदूपत्ता (46.97 प्रतिशत) और महुआ (31.86 प्रतिशत) मिलकर 79 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, यानी तेंदू पत्ता और महुआ मौसम आधारित होने पर भी यहाँ के अर्थतंत्र का मेरुदंड है। तीसरा प्रमुख उत्पाद चार (8.79 प्रतिशत) है। मात्रा मध्यम पर आगे आय–घनत्व उच्च मिलता है (तालिका–2)। चरोटा, बहेड़ा, वनतुलसी, इमली, वनजीरा, साल–बीज, लाख, शहद जैसे अनेक छोटे हिस्से वाले उत्पादों की लंबी कतार (लॉन्ग–टेल) उत्पाद बनाते हैं। इनकी मात्रा कम होते हुए भी खाद्य, औषधीय या विनिमय–मूल्य है और स्थानीय क्लस्टर–प्रसंस्करण से मूल्य–वृद्धि सम्भव है। संग्रहण–संरचना यह भी सूचित करती है कि महिला–श्रम (महुआ, ईंधन, ऋतु–संग्रह) और पुरुष–श्रम (तेंदू, परिवहन) का कार्य–विभाजन मौजूद है। सततता बनाए रखने की दृष्टि से आग व चराई नियंत्रण और सामुदायिक वन–निगरानी महत्त्वपूर्ण हैं, अन्यथा अतिसंग्रह/गुणवत्ता–ह्रास दीर्घकालिक जोखिम बना सकता है। नीति–स्तर पर भंडारण, प्राथमिक छँटाई और समयबद्ध खरीद से संग्रहण लाभ बढ़ेगा।

तालिका 2: देवानपटपर में प्रमुख वनोत्पादों का संग्रहण प्रतिशत

क्र.	वनोत्पाद का नाम	संग्रहण प्रतिशत
01.	महुआ	31.86
02.	डोरी	01.87
03.	इमली	01.23
04.	शहद	00.16
05.	चार	08.79
06.	बहेड़ा	01.61
07.	वनतुलसा	01.44
08.	वनजीरा	00.69
09.	साल बीज	00.37
10.	चरोटा	04.24
11.	लाख	00.77
12.	तेन्दूपत्ता	46.97

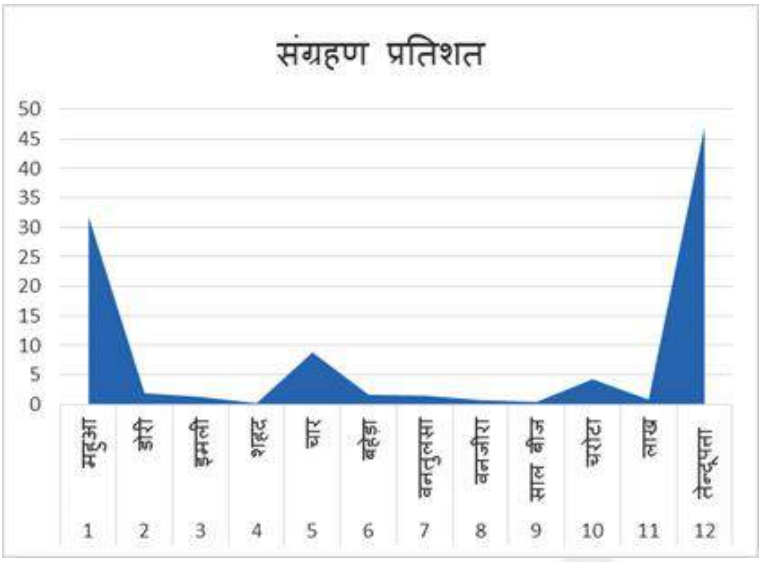

*(**स्त्रोत**: प्राथमिक समंक)*

तालिका 3 अधचरा NTFP गृह–उपभोग संरचना में महुआ (लगभग 88.28 प्रतिशत) का असाधारण प्रभुत्व है, बैगा खाद्य–सुरक्षा और सांस्कृतिक उपयोग की घरेलू–उन्मुखता दिखाता है; कठिन मौसम/रोज़गार का मौसमी अंतराल में यह 'खाध सुरक्षा–जाल' की तरह काम करता है। इसके विपरीत, तेंदूपत्ता (लगभग 5.95 प्रतिशत) और चार/चरौंजी (लगभग 5.75 प्रतिशत) का घरेलू उपयोग सीमित है; ये अपेक्षाकृत बाज़ार–उन्मुख उत्पाद हैं। शहद का उपभोग अति–कम (लगभग 0.02 प्रतिशत) दर्ज हुआ पर स्वास्थ्य/औषधीय मूल्य के कारण गुणवत्ता–ब्रांडिंग से इसका सामुदायिक लाभ बढ़ सकता है। विशिष्ट तौर पर उपभोग–प्रतिशत का हर भाजक घरेलू उपयोग के लिए होता है; इसे संग्रहण या MSP–राजस्व प्रतिशत से सीधे नहीं जोड़ा/घटाया जा सकता ये सूचि के संकेतक हैं। यह तालिका बताती है कि महुआ–केंद्रित आहार–संस्कृति आज भी सशक्त है; यदि भंडारण/प्रसंस्करण, स्वच्छता, फसल को कीटो से बचाने के लिए कीट–रोधी सुधरे तो पोषण–लाभ, खाद्य–सुरक्षा और अतिरिक्त विक्रय–अवसर तीनों बढ़ेंगे। महिला–SHG द्वारा वैल्यू–ऐडेड उत्पाद (लड्डू, सिरप, पेय पदार्थ) स्थानीय आय विविधीकरण में सहायक हो सकते हैं।

तालिका 3: अधचरा में प्रमुख वनोत्पादों का संग्रहण प्रतिशत

क्र.	वनोत्पाद का नाम	उपभोग प्रतिशत
01.	महुआ	88.28
02.	डोरी	00.00
03.	इमली	00.00
04.	शहद	00.02
05.	चार	05.75
06.	बहेड़ा	00.00
07.	वनतुलसी	00.00
08.	वनजीरा	00.00
09.	साल बीज	00.00
10.	चरोटा	00.00
11.	लाख	00.00
12.	तेन्दूपत्ता	05.95

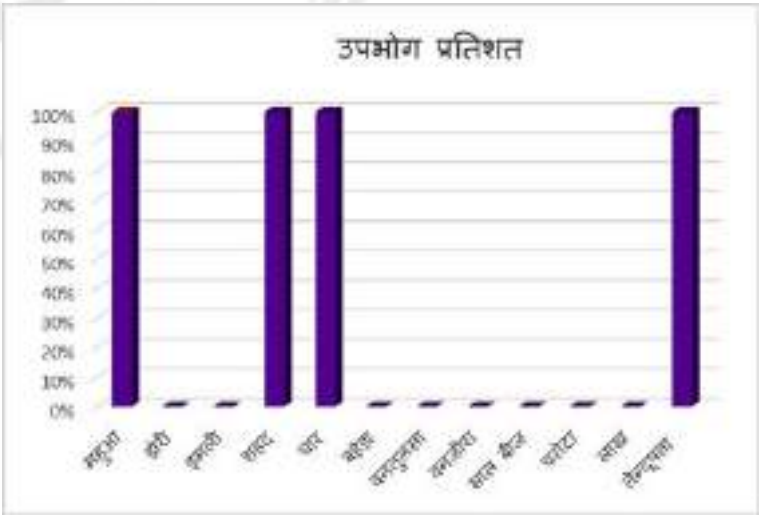

*(**स्त्रोत**: प्राथमिक समंक)*

तालिका 4 दमगढ़ MSP/औपचारिक विक्रय आय संरचना डैच/औपचारिक आय में चार/चरौंजी (लगभग 74.73 प्रतिशत) का अत्यधिक हिस्सा उसके उच्च प्रति–इकाई मूल्य और स्थिर मांग–श्रृंखला को दर्शाता है; यानी मात्रा कम, पर आय लाभ घनत्व अधिक। महुआ (लगभग 22.48 प्रतिशत) दूसरे स्थान पर है; इसका घरेलू–उपयोग बहुत ऊँचा होने से बाज़ार–आय का हिस्सा आनुपातिक रूप से घट जाता है– यदि श्रेणी में पैकेजिंग किया जाए तो अधिक लाभ होने से इनका राजस्व बढ़ सकता है। तेंदूपत्ता (लगभग 1.01 प्रतिशत) का MSP–हिस्सा बेहद कम दिखता है, जबकि संग्रहण में यह अग्रणी है; कारण है इसका अलग क्रय–तंत्र/ठेका, समयबद्ध भुगतान/काट–छाँट और मध्यस्थ बिचौलियों की लागत, जिससे औपचारिक MSP–बास्केट में अभिव्यक्ति सीमित रहती है। इमली/शहद/डोरी जैसी मदें लघु–हिस्सेदार हैं पर बड़े नाम वाले उत्पादों के साथ जोड़ना, गुणवत्ता–मानक, पारदर्शिता और डिजिटल भुगतान से इनका अनुपात सुधर सकता है। तालिका का समग्र संदेशः मूल्य–श्रृंखला में पारदर्शिता, स्थानीय प्रसंस्करण केंद्र, महिला–SHG आधारित उद्यम और समयबद्ध भुगतान तंत्र बैगा समुदाय की नक़द आय की स्थिरता को सार्थक रूप से बढ़ा सकते हैं।

तालिका 4: दमगढ़ में प्रमुख वनोत्पादों का संग्रहण प्रतिशत

क्र.	वनोत्पाद का नाम	उपभोग की गई मात्रा को उपभोग न कर MSP पर विक्रय की राशि (प्रतिशत)
01.	महुआ	22.48
02.	डोरी	00.08
03.	इमली	01.27
04.	शहद	00.43
05.	चार	74.73
06.	बहेड़ा	00.00
07.	वनतुलसा	00.00
08.	वनजीरा	00.00
09.	साल बीज	00.00
10.	चरोटा	00.00
11.	लाख	00.00
12.	तेन्दूपत्ता	01.01

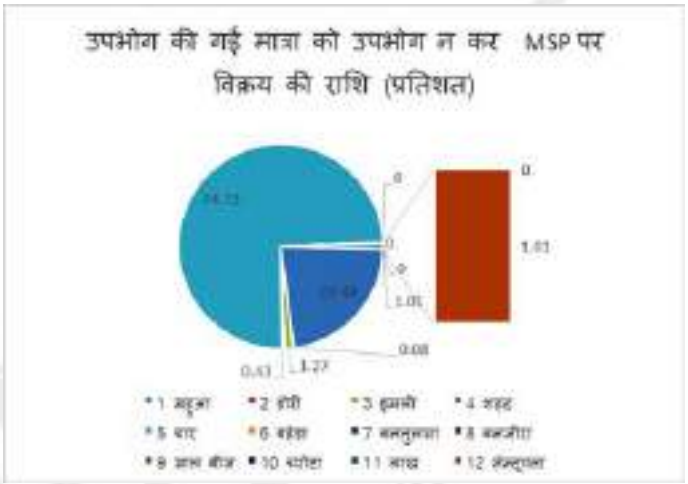

*(**स्त्रोतः** प्राथमिक समंक)*

चर्चा

शोध परिणाम दर्शाते हैं कि बैगा समुदाय की आजीविका बहु–आयामी और सांस्कृतिक पारिस्थितिकीय पर आधारित है। महुआ घरेलू पोषण, सांस्कृतिक अनुष्ठानों और "कठिन मौसम" में खाद्य सुरक्षा–जाल के रूप में केंद्रीय भूमिका में है; इसकी उच्च गृह–उपभोग हिस्सेदारी यही बताती है। चार/चरौंजी अपेक्षाकृत कम मात्रा में संग्रहित होकर भी उच्च मूल्य–घनत्व के कारण नक़द–आय का प्रमुख इंजन बनती है; यह संकेत देता है कि उत्पाद–विशिष्ट मूल्य–शृंखलाएँ अलग–अलग व्यवहार करती हैं। इसके विपरीत तेंदूपत्ता का संग्रह बहुत बड़ा है, पर MSP–आय में उसका योगदान कम दिखता है, क्योंकि उसका क्रय–वितरण अलग संस्थागत ढाँचे/ठेका–प्रणाली से संचालित होता है। यहाँ समयबद्ध भुगतान, कटौती/तौल–पारदर्शिता और परिवहन लागत मुख्य अवरोध हैं।

अध्ययन में 80 प्रतिशत परिवारों की उच्च वन–निर्भरता, 75 प्रतिशत का NTFP–आधारित नक़द–आय पर भरोसा, और 40 प्रतिशत का FRA के अंतर्गत अधिकार एक ओर "वन–जीविका सम्बन्ध" की मजबूती दिखाती है, तो दूसरी ओर नीतिगत–क्रियान्वयन की असमानता भी उजागर करती है। 60 प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्भरता में

"कमी" बताना वास्तव में विविधीकरण/अनुकूलन की प्रक्रिया है। मनरेगा, कृषि–मजदूरी, और सूक्ष्म उद्यमों का सहारा लेकर जोखिम फैलाना; यह वन–निर्भरता का क्षय नहीं, बल्कि जीविका विवरण का विस्तार है। सतत आजीविका की दृष्टि से यह सकारात्मक है, बशर्ते वन संसाधनों का सतत प्रबंधन और समुदाय के निर्णयाधिकार सुरक्षित रहें।

मूल्य–श्रृंखला दृष्टि से तीन बातें उभरती हैं: (i) उत्पाद–विशिष्ट रणनीति आवश्यक है महुआ के लिए भंडारण, स्वच्छ ड्राइंग, प्राथमिक प्रसंस्करण; चार के लिए गुणवत्ता–श्रेणी/पैकिंग और ब्रांडिंग; तेंदूपत्ता के लिए क्रय–प्रक्रिया की पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान। (ii) स्थानीय प्रसंस्करण हब तथा महिला–SHG उद्यमिता मूल्य–वृद्धि और आय–स्थिरता बढ़ा सकती हैं। (iii) बाज़ार सूचना व समयबद्ध डिजिटल भुगतान की पारदर्शिता से मध्यस्थ–निर्भरता घटेगी और सौदे की शक्ति बढ़ेगी। इन कदमों से महुआ जैसे "उपभोग–प्रधान" और चार जैसे "आय–प्रधान" उत्पादों के बीच संतुलित विवरण बन सकता है।

सामाजिक–लैंगिक आयाम भी महत्त्वपूर्ण हैं; महुआ/ईंधन/कंद संग्रह में महिलाओं की भूमिका केंद्रीय है, जबकि तेंदूपत्ता/परिवहन में प्रायः पुरुष अग्रणी हैं। नीतियाँ तब अधिक प्रभावी होंगी जब महिला–नेतृत्वित SHG/उत्पादक समूह को वित्त, प्रशिक्षण, गुणवत्ता–मानक और बाज़ार–लिंक से जोड़ा जाए। साथ ही, शिक्षा–स्वास्थ्य तक पहुँच की कमी (विशेषकर आवासीय विद्यालय, मातृ–स्वास्थ्य, संक्रामक रोग–निवारण) आजीविका की उत्पादकता और जोखिम–सहनशीलता दोनों को प्रभावित करती है; अतः मानव पूँजी में निवेश SLF के अनुरूप अनिवार्य है।

पारिस्थितिकीय–सांस्कृतिक सततता भी उतनी ही अहम है। "वन देवता", गोदना–कला और पारंपरिक औषधीय ज्ञान जैसे अवयव वन–निर्भर जीवन–दर्शन को अर्थ देते हैं। कोई भी बाह्य विकास/वाणिज्यिक हस्तक्षेप यदि इन सांस्कृतिक प्रतिमानों के साथ संवाद व समन्वय के बिना लागू किया गया, तो सामाजिक असंतुलन और समुदाय–विरोध पैदा हो सकता है इसलिए सामुदायिक वन प्रबंधन व संयुक्त वन प्रबंधन समिति (CFM/JFM) में बैगा प्रतिनिधित्व, सामुदायिक अधिकारों की वास्तविक मान्यता (FRA), और समुदाय–आधारित निगरानी व प्राकृतिक वन प्रबंधन पुनर्स्थापना (ANR/NFM) को केंद्र में रखना चाहिए।

अंततः मुख्य निष्कर्ष यह है कि बैगा आजीविका को मजबूती देने के लिए द्वि–मार्गी रणनीति चाहिए। एक ओर उत्पाद–विशिष्ट मूल्य–वृद्धि/बाज़ार–सुधार, दूसरी ओर अधिकार–क्रियान्वयन/मानव–पूँजी/सहभागी शासन का सुदृढ़ीकरण। यही संयोजन पोषण–सुरक्षा, आय–स्थिरता और सांस्कृतिक निरंतरता, तीनों लक्ष्यों को साथ लेकर चल सकता है।

सुझाव

नीतिगत रूप से, बैगा समुदाय की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए बहु–स्तरीय, समुदाय–केंद्रित हस्तक्षेप आवश्यक हैं सबसे पहले, MSP के साथ स्थानीय प्रसंस्करण केंद्र विकसित किए जाएँ, जहाँ चार/महुआ/इमली आदि की ग्रेडिंग–सॉर्टिंग–पैकिंग हो; गुणवत्ता मानक और डिजिटल भुगतान पारदर्शिता व समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करें। दूसरे, महिला–SHG उद्यमिता को संग्रह से लेकर मूल्य–संवर्धन, सूक्ष्म–वित्त और बाज़ार से जोड़ाकर सक्षम बनाया जाए, ताकि घरेलू श्रम का आर्थिक रूपांतरण और आय–स्थिरता बढ़े। तीसरे, FRA (2006) का प्रभावी क्रियान्वयन हो; सामुदायिक अधिकारों की मान्यता, अधिकारों का अभिलेखण तथा समयबद्ध विवाद निवारण तंत्र के साथ। चौथे, बाजार मूल्य सूचना और न्यूनतम–कमीशन व्यवस्था के साथ स्थानीय हाट–मंडी को सशक्त किया जाए; परिवहन व व्यापर में सहायता से खर्च कटौती/तौल अंतराल घटें। पाँचवें, शिक्षा–स्वास्थ्य पहुँच को जनजातीय भाषा–समर्थ शिक्षण, आवासीय छात्रावास, उप–केंद्र/मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा मज़बूत किया जाए। अंततः, सहभागी वन–प्रबंधन (CFM/JFM) 2.0 की ओर बढ़ते हुए बैगा प्रतिनिधित्व के साथ सह–निर्णय, समुदाय–आधारित पुनर्स्थापना (NFM/ANR) तथा जैव–विविधता/औषध–उद्यान स्थापित किए जाएँ; ताकि पोषण–सुरक्षा, आय–वृद्धि और सांस्कृतिक–पारिस्थितिक सततता साथ–साथ मजबूत हों।

बैगा समुदाय की आजीविका को सुदृढ़ करने हेतु नीतिगत रूप से MSP के साथ स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण केंद्र (चार/महुआ/इमली आदि) पर गुणवत्ता मानक और डिजिटल समयबद्ध भुगतान से पारदर्शिता व समयबद्ध निपटान आवश्यक है; महिला–SHG उद्यमिता को संग्रह से मूल्य–संवर्धन, सूक्ष्म–वित्त और बाज़ार पहुँच सम्बन्ध मजबूत किया जाए; FRA (2006) का प्रभावी क्रियान्वयन सामुदायिक अधिकारों की मान्यता और समयबद्ध विवाद–निवारण आत्मनिर्भर वन ग्राम शासन की कुंजी है; समय पर बाज़ार कीमतों की सूचना और न्यूनतम–कमीशन व्यवस्था के साथ हाट–मंडी सशक्त हों तथा परिवहन पूर्ति सहायता से कटौती व तौल बट्टा अंतराल घटें; शिक्षा–स्वास्थ्य पहुँच (जनजातीय भाषा–समर्थ शिक्षण, आवासीय छात्रावास, उप–केंद्र, चलित इकाइयाँ) और सहभागी वन–प्रबंधन (CFM/JFM) 2.0 में बैगा प्रतिनिधित्व, समुदाय–आधारित पुनर्स्थापना (NFM/ANR) व जैव–विविधता/औषध–उद्यान को प्राथमिकता दी जाए ताकि पोषण–सुरक्षा, आय–वृद्धि और सांस्कृतिक–पारिस्थितिक सततता साथ–साथ बढ़ें।

सीमाएँ: दुर्गमता, भाषाई दिककत व कुछ ऋतुओं में सीमित पहुँच; NTFP डेटा की मौसमी/वर्षीय उतार–चढ़ाव पर निर्भरता (जिससे बहु–वर्षीय औसत की आवश्यकता बनती है); तथा उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण के कारण निष्कर्षों का स्थानिक संदर्भ की ओर इशारा करते हैं कि व्यापक सामान्यीकरण में सावधानी अपेक्षित है और भविष्य में बहु–ऋतु/बहु–वर्षीय, तुलनात्मक तथा सूक्ष्म मूल्य–श्रृंखला अध्ययन उपयोगी सिद्ध होंगे।

निष्कर्ष

इस अध्ययन का केंद्रीय निष्कर्ष है कि बैगा (PVTG) समुदाय का जीवन–विशेषकर कवर्धा (देवानपटपर, अधचरा और दमगढ़) में वन संसाधनों के साथ एक त्रिकोणी संबंध पर टिका है, जीविका–सुरक्षा, सांस्कृतिक निरंतरता, और नक़द–आय। महुआ का स्थान घरेलू उपभोग, पोषण–सुरक्षा और संस्कारों में आधार–स्तम्भ जैसा है; इसका उच्च गृह–उपयोग बताता है कि कठिन मौसम, रोज़गार–रिक्ति और बाज़ार–अनिश्चितता में महुआ एक सुरक्षा–जाल प्रदान करता है। इसके विपरीत, चार/चरौंजी अपेक्षाकृत कम मात्रा में संग्रहित होकर भी अपने उच्च मूल्य–घनत्व के कारण डैच/औपचारिक विक्रय–आय का मुख्य इंजन बनती है। यह संकेत करता है कि उत्पाद–विशिष्ट मूल्य–श्रृंखला रणनीतियाँ आय–स्थिरता के लिए निर्णायक हो सकती हैं। तेंदूपत्ता का संग्रह बड़े पैमाने पर होने पर भी MSP–बास्केट में कम दिखना उसके अलग संस्थागत क्रय–तंत्र/ठेका–मॉडल और भुगतान–पारदर्शिता/कटौती/परिवहन जैसी बाधाओं की ओर इशारा करता है। कुल मिलाकर, परिणाम दर्शाते हैं कि बैगा समुदाय उच्च वन–निर्भर है पर साथ ही विविधीकरण (मनरेगा, कृषि–मजदूरी, सूक्ष्म–उद्यम) के माध्यम से जोखिम–फैलाव कर रहा है; यह वन–निर्भरता का क्षय नहीं, बल्कि जीविका–पोर्टफोलियो का विस्तार है।

इस पृष्ठभूमि में सतत् आजीविका आधारित ढांचा (SLF) का पाठ यह है कि प्राकृतिक (वन), सामाजिक (समुदाय/SHG), मानव (शिक्षा/स्वास्थ्य), भौतिक (भंडारण/परिवहन) और वित्तीय (MSP/डिजिटल भुगतान) पूँजियों का संतुलित सशक्तिकरण ही सतत् और न्यायसंगत विकास दे सकता है। अध्ययन के चार प्रमुख संकेतक–समूह (i) फील्ड–वर्क सारांश (उच्च वन–निर्भरता, आंशिक विविधीकरण, सीमित FRA–अधिकार, शिक्षा–प्रवास), (ii) NTFP संग्रह–प्रोफ़ाइल (तेंदू+महुआ का वर्चस्व), (iii) गृह–उपभोग (महुआ–केंद्रित), और (iv) MSP–आय (चार/चरौंजी–प्रधान) एक साथ मिलकर स्पष्ट करते हैं कि 'उपभोग–प्रधान' बनाम 'आय–प्रधान' उत्पादों की अलग अलग रणनीति चाहिए। उदाहरणतः, महुआ के लिए भंडारण–स्वच्छता–ड्राइंग व स्थानीय प्रबंधन, चार के लिए मूल्यवर्धन, और तेंदूपत्ता के लिए क्रय–प्रक्रिया पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान व पूर्ति ये सुधार सीधे समुदाय की नक़द आमदनी और सौदे को मजबूती बढ़ा सकती हैं।

अधिकार और शासन के मोर्चे पर FRA (2006) का प्रभावी क्रियान्वयन विशेषकर सामुदायिक अधिकारों की मान्यता, मैपिंग, रिकॉर्ड–ऑफ–राइट्स और समयबद्ध विवाद–निस्तारण बैगा समुदाय के स्वायत्त वन–शासन की कुंजी है। इसी तरह, सहभागी वन–प्रबंधन (CFM/JFM) 2.0 में बैगा प्रतिनिधित्व, समुदाय–आधारित पुनर्स्थापना (NFM/ANR) और जैव–विविधता/औषध–उद्यान जैसी पहलकदमियाँ पारिस्थितिकीय–सांस्कृतिक सततता को

सुदृढ़ करेंगी। महिला–SHG को संग्रह से लेकर मूल्य–संवर्धन, सूक्ष्म–वित्त, बाज़ार–संबंध और डिजिटल भुगतान से जोड़ना आय–स्थिरता और लैंगिक सशक्तिकरण दोनों हेतु निर्णायक रहेगा।

मूल्य–श्रृंखला पारदर्शिता (समय पर सही दाम, पारदर्शिता, न्यूनतम बिचौलियों हस्तक्षेप), परिवहन/तौल सुधार और भुगतान–समयबद्धता के बिना NTFP का सामाजिक लाभ सीमित रह जाता है; अतः स्थानीय संग्रह–बिंदु व गाँव स्तर पर प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करना उपयोगी होगा। समानांतर, शिक्षा–स्वास्थ्य पहुँच (जनजातीय भाषा–समर्थ शिक्षण, आवासीय छात्रावास, उप–केंद्र/मोबाइल इकाइयाँ) में निवेश मानव–पूँजी बढ़ाकर दीर्घकालीन आजीविका–क्षमता को मजबूत करेगा।

यह निष्कर्ष उभरता है कि बैगा–वन सम्बन्ध को आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक तीनों आयामों में साथ लेकर चलने वाली द्वि–मार्गी रणनीति (1) उत्पाद–विशिष्ट मूल्य–वृद्धि/बाज़ार–सुधार, और (2) अधिकार–क्रियान्वयन/मानव–पूँजी/सहभागी शासन ही सम्मानजनक एवं सतत विकास का वास्तविक पथ खोलती है। इस दिशा में मापनयोग्य सूचक (MSP–आधारित आय का हिस्सा, समयबद्ध भुगतान दर, महिला–SHG का कारोबार, महुआ की गृह–उपयोग बनाम विक्रय अनुपात, तेंदू के क्रय–समय/कटौती–घटनाएँ, FRA–अधिकारों का कवरेज) निर्धारित कर वार्षिक निगरानी की जाए, तो नीति–निष्पादन का असर पारदर्शी रूप से परखा जा सकेगा और बैगा समुदाय की आजीविका, पहचान और पर्यावरण, तीनों को दीर्घकाल में मजबूती मिलेगी।

संदर्भ सूची

1. एल्विन, वी. (1943) *The Baiga,* ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
2. गाड़गिल, म., गुहा, र. (1993) *This Fissured Land: An Ecological History of India,* University of California Press, California.
3. खाका, वर्जीनियस (2008) State, Society and Tribes: Issues in Post-Colonial India, पियर्सन एजुकेशन, नई दिल्ली।
4. भारत सरकार (2006) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. Mishra, A. (2021) Ecological livelihood and tribal communities in Central India, *Journal of Regional Studies,* 7(1), 55–70.
6. Sharma, D. C. (2018) Forest-based livelihoods in India, *Indian Journal of Tribal Studies,* 12(2), 34–48.
7. Arnold, J. E. M. & Ruiz-Pérez, M. (2001) Can non-timber forest products match tropical forest conservation and development objectives, *Ecological Economics,* 39(3), 437–447.
8. Chopra, K. & Kadekodi, G. K. (1997/1999) *Community-based management of common property resources in India: Issues and evidence,* Sage Publications, New Delhi.
9. Chambers, R. & Conway, G. (1992) Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century (IDS Discussion Paper 296) Birton, Institute of Development Studies.
10. कुमार, हरि शंकर; कुमार, अनिल; – कुमार, मुकेश (2023) अचानकमार–अमरकंटक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र की बैगा जनजाति की सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का नृजातिशास्त्रीय अध्ययन, *SHODH,* A Triannual Bilingual Peer Reviewed Refereed Research Journal of Art & Humanities, Vol- XX Issue No- 1, Jan–April- 2023, ISSN: 0970-1745, p. 03-18.

11. जनजातीय कार्य मंत्रालय (2012) वन अधिकार नियम, 2008 (संशोधित 2012), दिशानिर्देश, भारत सरकार, नई दिल्ली।

12. जनजातीय कार्य मंत्रालय (2020) विशेष रूप से दुर्बल जनजातीय समूह (PVTGs) पर प्रतिवेदन, भारत सरकार, नई दिल्ली।

13. जनजातीय कार्य मंत्रालय (2022) वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22, भारत सरकार, नई दिल्ली।

14. भारत की जनगणना (2011) ज़िला जनगणना पुस्तिकाः कबीरधाम (छत्तीसगढ़), भारत सरकार, नई दिल्ली।

15. छत्तीसगढ़ शासन (2022) कबीरधाम ज़िला सांख्यिकी हैंडबुक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

16. Forest Survey of India (FSI) (2021) India State of Forest Report 2021, FSI, Dehradun.

17. Tribal Research & Training Institute, Chhattisgarh (2021) Baiga Tribe: Profile and Development Strategies, TRI, Raipur.

18. Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation (CGMFPFED) (2018–2023) वार्षिक प्रतिवेदन एवं MSP संचालन अभिलेख, सीजीएमएफपीएफईडी, रायपुर।

19. TRIFED (2020) MSP for MFP, Operational Guidelines (Revised) TRIFED, New Delhi.

20. FAO (2011) Non-wood Forest Products: Policy and Value Chains, Food and Agriculture Organization, Rome.

****